भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1296
सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

बेरोजगारी उन्मूलन हेतु कदम

1296. श्री नारायण तातू राणे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी की मांग और आपूर्ति को डिजिटल बनाने के लिए कोई पहल की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल की स्थापना के उद्देश्य का ब्यौरा क्या है और महिला/पुरूष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी रिक्तियां भरी गई हैं; और
(ङ) इस पोर्टल पर नौकरियों की सूची बनाने का दायरा और सीमा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करना है ताकि युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सक्षम बनाकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

एनसीएस पोर्टल पर अंतिम भर्ती आँकड़े सूचित करना अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, 10.07.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 6.3 करोड़ से अधिक रिक्तियाँ उपलब्ध थीं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिक्तियां https://www.ncs.gov.in/_layouts/15/ncsp/ViewStaticReport.aspx पर देखी जा सकती हैं।

****